The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seven minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) *In the Chair.*

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

Village Public Telephones

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now clarifications on the statement regarding village public telephones. Shri Ish Dutt Yadav — not here. Shri Nilotpal Basu — not here. shri Moolchand Meena. आप संक्षेप में बोलिए।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे भी संक्षेप में ही बोलता हूं। संचार मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य ग्रामीण टेलीफोन के कार्यक्रम के संबंध में दिया है, उसमें कहा है कि फील्ड यूनिटों की रिपोर्टों की सत्यता स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराई जाएगी। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांव में जो टेलीफोन लगे हुए हैं उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आप इसकी जांच कराएंगे तो पाएंगे कि ऐसे किसी भी विवाद की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होगी, जितनी दयनीय स्थिति आपके टेलीफोन की है।

महोदय, मैं राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर की बात आपके सामने कहना चाहूंगा। वहां मंडराल, कर्णपुर और मासलपुर, जो उप तहसील के हैडक्वार्टर हैं और जो एक कस्बे टाइप के बड़े गांव हैं उनमें टेलीफोन की व्यवस्था वर्ष 1980 से है, लेकिन यह टेलीफोन एक तो जिस दिन लगे उस दिन चले और उसके बाद आज तक भी इन टेलीफोनों पर बात नहीं हुई। यह तो उप तहसील की स्थिति है। आपने गांवों के लिए वक्तव्य दिया, अच्छी बात है, लेकिन आज उप-तहसील की स्थिति यह है। जो टेलीफोन गांव में एक बार लगता है उसको और जो खराब हो जाता है उसको ठीक करने की बात तो होती ही नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव के अंदर जो सार्वजनिक टेलिफोन लगते हैं, उनकी स्थिति यह है कि जिले के जो अधिकारी हैं, बिना कारपन के गांव के किसी आदमी के यहां टेलिफोन लगाते ही नहीं है। आज स्थिति यह है कि "सवाई माधोपुर" के "करौली" डिवीजन के अन्दर गांव के नाम पर जंगल में जो खनन का काम होता था, उन खननों पर टेलिफोन लग गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं, कराइए, अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं। कि यह जांच कब तक हो जाएगी? इस जांच के क्या, किस-किस को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यह बात आप स्पष्ट कर दें क्योंकि आप यहां से, सैंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर तो कानून बना देते हैं लेकिन निचले स्तर पर जाकर वे कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं यह बात मैं आपको प्रोक्टिकल रूप में बता रहा हूं कि एक-एक टेलिफोन, जो गांव में सार्वजनिक रूप से लगता है, उस पर क्षेत्रीय अधिकारी दो-दो हजार रुपए लेता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसको कैसे रोक पाएंगे? गांव के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, वे बड़ी अच्छी हैं क्योंकि आप भी ग्रामीण हैं, इसलिए आप उनके लिए ऐसी-ऐसी नीतियां बनाना चाहते हैं ताकि गांव के लोगों को वास्तविक रूप में टेलिफोन मिले लेकिन अपनी नीतियों को वास्तविक रूप देने के लिए क्या आपने कोई मॉनिटरिंग सेल अलग से गांव के टेलिफोनों की जांच के लिए बनाया है और उस सेल में क्या आपने उन लोगों को, जो जनता के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, रखा है जिससे जांच वास्तविक रूप में हो सके? मैं कहना चाहता हूं कि आप जिला स्तर पर, डिवीजन स्तर पर जनप्रतिनिधियों की कमेटियां बनाएं ताकि दूर-संचार के क्षेत्र में अगर कहीं कोई करप्शन हो रही हो तो उसकी जांच जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी करे। यह आप तय करें तभी आपके वक्तव्य की मंशा पूर्ण हो पाएगी, यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Chairman, Sir, I would like to know what prompted the Minister to make this statement. I do not think there is any substance in the statement. I think he was prompted by the questions we raised in the House. The scheme — Village Public Telephones, was announced by Shri Rajesh Pilot. It was a unique scheme. This was done to remove the pressure on the demand for telephones. The Village Panchayat Group Telephone Scheme was a model scheme. Instead of conducting an inquiry, in both the 'a' and 'b' paragraphs of the statement, he says that he is going to ask the CBI to

investigate. We have no objection to this. Why should he waste the time of the House by making such statements? Let them ask the CBI to investigate and then come before the House with facts. We have nothing against the Government if the Government smells a scam here and there. We have seen what happened when Airbus — A-320 aircrafts were grounded. Fourteen of them were grounded for nine months. The whole country suffered a loss of Rs. 200 crores. Who was responsible for this? There is no accountability. It will not serve any purpose if we have to just make statements and entertain the gallery.

Let the Minister come to the house with facts. Let the Minister say that he had appointed the CBI to inquire into it and these were the findings and these were the people who were caught in the scam, rather than make statements which have no relevance. The scheme was wonderful. There is corruption in the Telecom Department throughout the country. Nobody can say that there is no corruption. The PCOs have been cornered by the staff and the family members of the staff of telephone exchanges. Meters are being tampered with in telephone exchanges. We made umpteen complaints. This can only be checked by the Telephone Advisor Committee. In my State, the tenure of this Committee expired in May last year. I raised this matter in the House. We also gave them a list. But nothing happened. Corruption is being compounded by this Government. When we, MPs, give them a list, they are not bothered about it. They collect names from the streets. This is the charge made against this Government.

So I do not know what the Minister is going to tell us by this statement. I do not find any sense in the statement. He is likely to select an institute for investigation; CBI will be asked. I do not know what the Government is trying to tell us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the hon. Minister explain. The Statement does not seem to give full details. The hon. Minister can explain it in his reply.

SHRI JOHN F. FERNANDES: He is only giving information to the House that he is intending to do so and so...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no what you are saying is absolutely right. The hon. Minister should have mentioned what the complaint was. Then on the basis of that complaint what action he has taken, he has to tell us. The Statement is not giving full facts.

SHRI JOHN F. FERNANDES: I presume that there was a Starred Question in this House and the House was agitated that the village telephones are not functioning because the telephones are cornered by the PCOs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no, that should come in the statement itself. The details have to come in the Statement also.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Nothing is there, so we are just inferring it.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): The reason was that the elder brother of Dr. Jagannath Mishra died due to non-functioning of telephones in Balua district. Dr. Jagannath Mishra and I raised this issue in this House, in this session and we demanded a Statement on the village telephone system. So, that is the reason, but whatever has come is too small.

SHRI JOHN F. FERNANDES: No. Mr. Vice-Chairman, what we are saying is that most of the village telephones are not functioning because the telephones are cornered by the PCOs and their staff. That is what I am saying. So let the Minsiter come before the House with information and conduct an enquiry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): What Mr. John F. Fernandes is saying is that if you come out with a Statement, it is all right. But what made you to come to this House with a Statment also should be narrated in this Statement. That is not there. Shri S.S. Ahluwalia.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री जी ने विलेज टेलीफोन के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य दिया है। सदन जानता है कि इस बारे में वक्तव्य देने की मांग हमारे माननीय सदस्य डा० जगन्नाथ मिश्र ने की थी। कुछ दिन पहले जब बलुआ-बाजार में वहां का टेलीफोन काम नहीं कर रहा था, एस०टी०डी० काम नहीं कर रहा था, तब उनके बड़े भाई को हार्ट-अटैक हो गया था, उस समय टेलीफोन खराब होने की वजह से किसी डाक्टर से कांटेक्ट नहीं किया जा सका। अगर डॉक्टर से कांटेक्ट हो पाता तो शायद दरभंगा से या मुजफ्फरपुर से या पटना से डॉक्टर भेजा जा सकता था। टेलीफोन के काम न करने के कारण पेशेंट को मरने के लिए बाध्य होना पड़ा।

महोदय, हमने सदन में मांग उठाई थी कि जैसे डेवलपमेंट के लिए और बिजनैस के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है, उसके साथ-साथ गांवों में भी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन की जरूरत है क्योंकि हर गांव का बेटा कहीं फौज में है, कहीं इंडियन एयरलाईंस में है, कहीं पब्लिक सैक्टर में है, कहीं व्यापारी है या कहीं कुछ काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है, उनकी सुविधा के लिए भी टेलीफोन चाहिए। यह मांग सदा से रही है और हर संचार मंत्री ने वचन दिया कि हम गांवों में टेलीफोन की सुविधा देंगे।

महोदय, हमारा देश गांवों का देश है। एक छोटे से किसान के पास भी जब कोई खरीदार आता है या अनाज मंडी के लोग आते हैं अनाज खरीदने के लिए तो उसको भी सही भाव पता लगाने के लिए टेलीफोन की जरूरत है। चाहे वह साग-सब्जी हो, दूध हो या अनाज हो, इन चीजों के भाव किसान को टेलीफोन के माध्यम से पता लग सकते हैं। यह एक बहुत अच्छी पहल थी संचार मंत्री की, उन्होंने इस बारे में आदेश भी दिए, मीटिंग और कांफ्रेंसें भी कीं पर अब तक वे इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके।

महोदय, जहां तक बिहार में पंचायत लेवल पर टेलीफोन लगाने की बात है, हर पंचायत का मुखिया अब तक सैकड़ों बार लिखकर दे चुका है कि हमारे इलाके में टेलीफोन लगाया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं है। केन्द्र सरकार का जो निर्देश जाता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जो वहां के जी०एम० हैं और टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं देते। इंडस्ट्रियल ऐरिया में तुरंत टेलीफोन मिल जाता है लेकिन गांवों में नहीं मिलता। अभी एनाऊंस किया गया था कि स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ आवेदन पर टेलीफोन दिया जाएगा, तत्काल दिया जाएगा पर आप खुद देखिए कि कितने स्वतंत्रता सेनानी आपके पीछे घूम रहे हैं और उनको अभी तक टेलीफोन नहीं मिला है। मेरी आपसे यह भी मांग है कि आपके विभाग में यदि कोई चोरी हुई है, कोई बेईमानी हुई है तो आप उसकी निष्पक्ष खोजबीन करें और उसकी इंक्वायरी कराएं।

सी०बी०आई० से इंक्वायरी कराएं। सी०बी०आई० के ऊपर कोई और हो तो उससे भी करालें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हमारे देश का पैसा जो जनता के उपभोग का है उस पैसे का दोहन करके वह अपनी सम्पत्ति को बढ़ाए। यह राष्ट्र की सम्पत्ति है और राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा फर्ज है और उस फर्ज को निभाते हुए अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है आपको। परन्तु मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि पंचायत लेविल पर टेलीफोन देने का जो वायदा संचार मंत्रियों का है, वह कब तक पूरा कर देंगे, यह बताने की कृपा करें? खासकर के बिहार में पंचायत लेविल में भी मैं आपसे कहूंगा कि कटाव क्षेत्र को पकड़िए पहले। गंगा के किनारे-किनारे, गंडक के किनारे-किनारे, महानदी के किनारे-किनारे और जो कटाव क्षेत्र में लोग रहते हैं और दूरदराज में कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, जहां-जहां आपके पोस्ट आफिसेज हैं, सब-पोस्ट आफिसेज पर एक-एक पी०सी०ओ० की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, यह बताने की कृपा करें? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको आपने कनेक्शन देने का वायदा दिया हुआ है, वह कब तक पूरा कर देंगे?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, Shri Thalavai Sundaram. Mr. Sundaram, please be brief. Please conclude within two minutes.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. chairman, Sir, I belong to Thovali village in Kanyakumari district of Tamil Nadu. Last week I went to my village and I wanted to contact somebody. But I was told that my telephone was out of order for more than one week. As far as telephones in villages

are concerned, they are the main, vital links with outside world. Unfortunately, most of the village telephones either in hospitals or schools or anywhere are not properly working. The Department people don't attend to telephone complaints. It is particularly so in Kanyakumari district. They never attend to telephone complaints immediately. The Minister said in his statement that he would order a CBI probe. But the CBI people would not come to villages. They sit in the headquarters. They never come to the village areas.

I think a Committee comprising Lok Sabha and Rajya Sabha Members as also the concerned Panchayat Presidents to see whether the village telephones are functioning properly. Secondly, the Minister should clarify as to what exactly is the application fee for telephones in different places because the fee varies from Rs. 1,000/- to Rs. 3,000/- depending upon the area. Unless local Committees are cosntituted nominating the concerned MPs and the Panchayat Presidents to investigate into the functioning of the village telephones, there is no use blaming the Central Governemnt or the CBI. All of us must co-operate so as to see that communicaiton system in the villages is strengthened. If there are no dependable telephones in the villages, we will not be able to attend to our works, whether it is a marriage, political work or any emergency. I request the hon. Minister to take necessary action, particularly in regard to the problems of Kanyakumari district.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Jalaludin Ansari. Mr. Ansari, please confine yourself to the Minister's statement because most of the Members are not doing so. You must also be very brief.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री जी ने जो अपने बयान में यह मंशा दिखलाई है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच किसी एजेंसी से कराना चाहते है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उस एजेंसी को आप तय कीजिए और सदन को बताइए कि किस एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं। वह प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद हो या कोई फिर दूसरी एजेंसी हो। आपके बयान के दूसरे पैरा में कहा गया है कि—सी०बी०आई० को कहा जाएगा। इसका मतलब है कि अभी निश्चित नहीं किया गया है कि किस एजेंसी से जांच कराएंगे। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इस गड़बड़ी की जांच के लिए आप कोई एजेंसी तय करें और उससे हम लोगों को भी अवगत कराएं। यह सर्वविदित है कि ...(व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि कहा जाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him clarify that.

श्री जलालुदीन अंसारी: मेरा कहना है कि जिस एजेंसी से भी हो स्पष्ट करें कि वह किस एजेंसी से कराने जा रहे हैं। अभी निश्चित नहीं है। मैं चाहता हूं कि निश्चित हो जाए कि किस एजेंसी के द्वारा जांच होगी? यह सही है कि हमारे बिहार के गांवों में टावर खड़ा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उस टावर के जरिए टेलीफोन कब लगेंगे? पंचायत के सामुदायिक भवन में, पंचायत भवन में या पोस्ट ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, यह हमारे साथी अहलुवालिया जी ने भी कहा। मैं भी बिहार को बिलांग करता हूं और बिहार में इस की आम तौर पर कठिनाई है। इसी तरह की स्थिति दूसरे राज्यों में भी होगी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने जो टेलीफोन देने का वायदा किया है, उसको लागू करने के लिए कार्यवाही कीजिए और इसकी जांच अवश्य कराइए। गया जैसे शहर में कभी-कभी चार सौ-पांच सौ टेलीफोन डेड हो जाते हैं और महीनों डेड रहते हैं। गया एक प्रमंडल है, कमिश्नरी है। मेरा टेलीफोन भी दो महीने तक बंद रहा तो इनके विभाग में भी गड़बड़ी है। ढाई सौ-तीन सौ टेलीफोन हमेशा ही खराब रहते हैं। मैं गया में रहता हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे देखिए। गया की एक इंपोर्टेंस है, महत्व है, सभी लोग इसको जानते हैं। दूसरे, पिछले दो-तीन महीनों से बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि पता ही नहीं चलता कि इतने टेलीफोन कब किए गए? मैं तो टेलीफोन पर लॉक भी लगा कर रखता हूं।

کھڑا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ٹیلیفون کب لگیں گے۔ پنچایت کے سامنے ایک بھون میں۔ پنچایت بھون میں یا پوسٹ آفس میں ٹیلیفون کنکشن نہیں مل پا رہا ہے ہیں۔ اور بہار میں اسی کی عام طور پر کھوٹینا ئی ہے۔ اسی طرح کی اشتھ دوسرے راجیوں میں بھی ہوگی۔ تو میں مانیئے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ آپنے جو ٹیلیفون دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسکو لاگو کرنے کیلئے کارروائی کیجئے اور اسکی جانچ ضرور کرا لیجئے۔ گیا جیسے شہر میں بھی کبھی چار سو پانچ سو ٹیلیفون ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اور مہینوں ڈیڈ رہتے ہیں۔ گیا ایک پرمنڈل ہے کمشنری ہے۔ میرا ٹیلیفون بھی دو مہینے تک بند رہا تو اسکے دھیان میں بھی گڑبڑی ہے۔ ڈھائی سو تین سو ٹیلیفون ہمیشہ ہی خراب رہتے ہیں۔ میں گیا میں رہتا ہوں اسلئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے دیکھئے۔ گیا کی ایک امپارٹنس ہے۔ مہتو ہے۔ سبھی لوگ اسکو جانتے ہیں۔ دوسرے پچھلے دو تین مہینوں سے بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنے ٹیلیفون لگ کب گئے۔ میں تو ٹیلیفون پر لاک بھی لگا کر رکھتا ہوں۔]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Amariji, we will

†[شری جلال الدین انصاری "بہار": آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ سنچار منتری جی نے جو اپنے بیان میں یہ منشا دکھلایا ہے کہ اگر میرے سارے ٹیلی فون میں جو گڑبڑی ہوئی اسکی جانچ کسی ایجنسی سے کرانا چاہتے ہیں میں انسے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایجنسی کو آپ طے کر دیجئے اور سدن کو بتلایئے کہ کس ایجنسی سے جانچ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ پرشاسنک اسٹاف کالج حیدرآباد ہے یا کوئی پھر دوسری ایجنسی ہے۔ آپکے بیان کے دوسرے پیرا میں کہا گیا ہے کہ سی۔ بی۔ آئی کو کہا جائیگا۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ ابھی نشچت نہیں کیا گیا ہے کہ کس ایجنسی سے جانچ کرائینگے تو میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ اس گڑبڑی کی جانچ کے لئے آپ کونسی ایجنسی طے کریں اور اس سے ہم لوگوں کو بھی اوگت کرائیں۔ سرودت ہے کہ ... "مداخلت" ...]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him clarify that.

†[شری جلال الدین انصاری: میرا کہنا ہے کہ جس ایجنسی سے بھی ہو اسپیشلی کریں کہ وہ کس ایجنسی سے کرانے جا رہے ہیں۔ ابھی نشچت نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ نشچت ہو جائے کہ کس ایجنسی کے ذریعے جانچ ہوگی یہ صحیح کہ ہمارے بہار کے گاؤں میں ٹاور

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

discuss it on a later date. You seek clarifications on the statement.

श्री जलालुदीन अंसारी: तो इसलिए यह जो गड़बड़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप यह जांच कराएं, एजेंसी तय करें और सदन को बताएं क्योंकि जांच होनी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन देने का इनका जो वायदा है, उसे वे पूरा करें, इतना ही मुझे कहना है।

†[श्री جلال الدین انصاری: تو اسلئے یہ جو گڑبڑی ہے اسکو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ یہ جانچ کرائیں۔ ایجنسی طے کریں اور سدن کو بتائیں کیونکہ جانچ ہونی ضروری ہے گرامین چھیتروں میں ٹیلیفون دینے کا انکا جو وعدہ ہے۔ اسے وہ پورا کریں۔ اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Nilotpal Basu. You were not there when your name was called.

SHRI NILOTPAL BASU: I am sorry, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please be brief and ask only pointed questions.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, firstly, I thank the Minister for having responded promptly to the issues that had come up in the House. Now, the inquiry will be in two parts. Of course, I do not understand what the intention is. Anyway, one part of the inquiry will be dealt with by some technical agencies like the Administrative Staff College, Hyderabad or one of the Indian Institutes of Management. The other part is, if any criminal aspect is involved, it will be inquired into by the CBI. there are two things. Of course, the problem is there at both the levels. We have discussed at length the criminal aspects of it. Earlier some cases had also come up and on the basis of that the CBI had taken up certain cases. Certain firms which were dealing with this particular equipment —MAAR and other systems — had been indicated, charge-sheeted and so on and so forth. The second part relates to the policy decisions that were taken and on the basis of which there might have arisen certain problems.

My feeling is that this decision of the Government should have come a bit earlier. Why was this decision on conducting an inquiry not taken earlier? It was very clear that there had been large scale corruption, particularly in terms of equipment that was necessary for installation of village public telephones. The Minister himself has gone on record to say in this House that in the last three years so far as targets pertaining to installation of village telephones are concerned, the DOT, notwithstanding its good performance in some sectors, has failed to achieve the targets.

The targets were affected. So, I would like to know whether that process led to shortfall in achievement of targets. Normally, one would expect that that would have affected the quality of service also. So, I would like to know as to why such an inquiry was not conducted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay.

SHRI NILOTPAL BASU: Then, there is another point...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): At 2.30, we have to start the Private Member's Business.

SHRI NILOTPAL BASU: I want to know as to which agency will also go into the kind of tendering and other things which were there and the quality of equipment which were taken. Continuously, in the last three-four years, the price had been falling and we were given to understand that the price fall was not always natural. It was artificial. ...*(Interruptions)*... Apparently, the price advantage which the DOT was showing

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

whether that had actually been reflected in terms of quality of equipment supplied which had resulted in such a situation. So, the hon. Minister may kindly clarify all these points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now it is 2.30 and we have to take up the Private Members' Business. If the House so agrees, we can take ten more minutes to enable the Minister to reply. Then, we will take up the Private Members' Business. If the House so desires, we will adjust that time later.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Sanatan Bisi. There is only one minute for you. After that, the Minister will reply.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, so far as the second part of the statement is concerned, our Government is very transparent and accountable. I would like that the Minister should set some deadline by which the CBI inquiry will be conducted. I would also like that the report of the CBI inquiry should be laid on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Minister of Communications.

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी है, उससे निश्चित रूप से जो सरकार का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी इसलिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद, क्योंकि मैं भी उसी पृष्ठभूमि का ही हूं, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की ओर गया है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का कार्य इस विभाग में उपेक्षित ही रहा है। पिछले कई वर्षों में लक्ष्य का 50 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए प्रारम्भ में ही हमने इसके लिए अलग से बजट एलोकेशन किया था और इसके लिए मॉनिटरिंग सैल भी बनाया गया था। जैसा हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जानने का प्रयास किया था, हमने पहले ही मॉनिटरिंग सैल बना दिया था और इस वीकली उसकी रिपोर्ट मंगा रहे थे। अब यह वर्ष समाप्त होने को है लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय सदस्यगण असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, करीब-करीब हम भी उन्हीं से स्वयं को संबद्ध करते हैं क्योंकि हम भी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हमको यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की उपयोगिता आज बढ़ती जा रही है, जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री अहलुवालिया जी भी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी उपयोगिता दिन-पर-दिन बढ़ रही है। क्यों ऐसा हुआ? जब हमने यह चीजें इन्ट्रड्यूस की तो शुरू के सारे इंस्ट्रूमेंट फेल कर गये। क्यों फेल कर गये? इसकी जांच बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो यह हमारी जानकारी में आया और जो ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी है, उसने भी इस बात को नोटिस किया इसलिए हमने कल निर्णय किया। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे में फील्ड यूनिटें जो हमें रिपोर्ट भेज रही हैं, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे क्योंकि हमको रिपोर्ट भेजी गयी थी कि 70 प्रतिशत इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं और जो फीड बैक मिल रहा है, उससे पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं थे। उस विभाग से ही अगर जांच करवाई जाती तो उस पर फिर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो सकता था इसलिए हमने निर्णय किया कि इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करवा ली जाए लेकिन साथ ही साथ हमने यह इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने में जांच की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए और लक्ष्य पूरा हो, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के काम में और तेजी आए और वह काम भी चलता रहे और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए एजेंसी के द्वारा अलग से जांच होती रहे।

हमारे अंसारी साहब ने अभी कहा था कि सीबीआई को कहा जाएगा, यह एक आश्वासन है और सरकार यह कहने के बाद मुकर नहीं सकती है। कुछ फारमल्टीज हैं वह पूरी करनी पड़ती हैं, वह हो रही हैं और जल्दी होंगी। वह इस बात की जांच करेगी कि शुरू में जो एमएआरआर या दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्यों फेल हो गये, उनमें कौन-सी टेक्नीकल खराबी थी, कोई फाइनेन्सियल उसमें इरेगुलरिटी हुई थी कि नहीं हुई थी, कोई लीगल इरेगुलरिटी हुई थी कि नहीं हुई थी और जब से एमएआरआर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से अब तक कि फाइनेंशियल, टेक्निकल या और भी उसमें कोई इरेगुलरिटी है, अनियमितता है तो उसकी जांच सीबीआई

करेगी और उसी के आधार पर कारवाई होगी। सुधार तो एक निरन्तर प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि इससे इस दिशा में थोड़ा सुधार भी आयेगा।

महोदय, हम उसमें और भी कुछ सुधार करना चाहते हैं। उसको भी मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा। उस पर हम अभी विचार कर रहे हैं और आप लोगों की राय होगी तो उस पर निर्णय लेंगे। हम खासतौर से ग्रामीण टेलीफोन के बारे में सुधार करना चाहते हैं। जिलों को और जिले के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। माननीय सदस्यों को भी हमारे विभाग के अधिकारी सूचित करेंगे कि इतने टेलीफोन ठीक हैं और इतने खराब हैं जिससे माननीय सदस्यों को यह जानकारी रहेगी कि वह ठीक बता रहे हैं। अगर वे किसी गांव में जायें और टेलीफोन ठीक न हो तो उनसे कंपलेंट कर सके। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम जारी करने जा रहे हैं। यह जो सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है उसमें विभिन्न निर्माताओं की मदद से खराब पड़े एमएआरआर के उपकरणों की मरम्मत करना, अनुरक्षण रहित बेटरियों का इस्तेमाल करना आदि। एक नई बैटरी आ गई है जिसमें मेंटीनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें डिस्टल्ड वाटर नहीं डालना पड़ता है, वह इंट्रोड्यूस की जा रही है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की मरम्मत के लिए पिछले चार महीने के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया है लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने के कारण हमको यह कदम उठाना पड़ा है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के कार्यकरण की मानीटरिंग करने में राज्य सरकारों का सहयोग लेने का प्रस्ताव है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्वतंत्र एजेन्सी की रिपोर्ट की जानकारी हमको तो मिलेगी ही लेकिन साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और हमारे डिपार्टमेंट के लोग माननीय सदस्यों से सम्पर्क करेंगे जिससे हमें एक अलग फीड बैक मिलेगा कि वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और स्वतंत्र एजेन्सी अपना अलग से कार्य करेगी। विशेषरूप से हमको जो यह निर्णय लेना पड़ा वह इसी वजह से लेना पड़ा कि जो अपेक्षाएं ग्रामीण लोगों की, जनप्रतिनिधियों की थी, उन अपेक्षाओं को पूरी तह से हम कह सकते हैं कि पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक था कि जो कार्य है उसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पूरी मेहनत करते हुए इन चीजों की भी एक स्वंतत्र एजेन्सी से जांच करवा ली जाए। स्वतंत्र एजेन्सी जो हमको रिपोर्ट देगी उसमें भी हमने तीन चीजों को खासतौर से रखा है। पहला है कि कार्य कर रहे ग्रामीण सार्वजनकि टेलीफोनों की संख्या का सत्यापन करना। दूसरा मानीटरिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रिया संबंधी सुझाव देना और तीसरा स्थानों और अन्य पैरा मीटरों में नीति संबंधी परिवर्तनों का सुझाव देना। उस एजेन्सी से हम यह भी कहेंगे कि इन तीन पैरा मीटर्स के बारे में भी हमको अपनी राय दे। इसी के साथ-साथ सीबीआई जांच करेगी इसके बारे में हमने पहले संक्षेप में बता दिया है। एमएआरआर उपकरणों के घटिया काम करने और कुछ ऐसे उपकरण जिनकी मरम्मत संभव नहीं है, ऐसे उपकरण क्यों खरीदे गये, इसके बारे में सीबीआई जांच करेगी।

संचार स्थायी संसदीय समिति में एमएआरआर के बारे में प्रश्न उठाया गया था और संसदीय समिति की भी यह अपेक्षा थी कि इसमें जांच कराई जाये। इन सभी कारणों से और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सिर्फ वहां पर टावर न खड़े कर दिये जायें, वे टावर काम भी करें इसलिए निर्णय लेना पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं पहुंचाने का विभाग का लक्ष्य है उसमें जो कुछ दिक्कतें आ रही थीं इससे कुछ मदद मिलेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग बढ़ेगा और एक पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जो हम सब लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा कर पायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Minister, I would like to observe that while discussing this issue, hon. Members made certain complaints with regard to the functioning of telephones. You please take care of this aspect. Secondly, while making a statement like this, you should also mention the background on the basis of which it emanates. This is missing in the present statement. Please take note of it also. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, what about the report of the Inquiry Committee? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister may take his own decision in this regard. I cannot force him.